

ईयू प्रतिबंध और मौलिक कानूनी सिद्धांतों का क्षरण:

हुसेन डोगू एक पत्रकार हैं जिनका कार्य राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषयों पर केंद्रित रहा है, जिसमें फिलिस्तीन और यूक्रेन पर रिपोर्टिंग शामिल है। उनकी रिपोर्टिंग और सार्वजनिक टिप्पणियों ने यूरोपीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है, और उन्हें ईयू प्रतिबंध ढांचे के तहत प्रतिबंधात्मक उपायों के अधीन किया गया है, विशेष रूप से **काउंसिल रेगुलेशन (ईयू) 2024/2642**, जैसा कि संशोधित (विशेष रूप से रेगुलेशन 2025/965 द्वारा उनकी सूचीकरण को प्रतिबिंबित करते हुए), संघ और उसके सदस्य राज्यों को अस्थिर करने वाली कार्रवाइयों से संबंधित। उल्लेखनीय है कि श्री डोगू पर **कोई आपराधिक अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है**, न ही किसी अदालत ने पाया है कि उन्होंने घरेलू या अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। उन पर लगाए गए प्रतिबंध कार्यकारी उपाय हैं, जो आपराधिक कार्यवाही के ढांचे के बाहर अपनाए गए हैं।

श्री डोगू के खिलाफ सार्वजनिक रूप से व्यक्त आरोप आपराधिक आचरण से संबंधित नहीं हैं, बल्कि उनके कार्य और भाषण को यूरोपीय संघ की विदेश और सुरक्षा नीति उद्देश्यों के तहत कथित रूप से अनुचित, हानिकारक या अवांछनीय मानने की आकलन से संबंधित हैं। इन आकलनों की किसी प्रतिपक्षीय न्यायिक प्रक्रिया में परीक्षा नहीं की गई है, न ही श्री डोगू को किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष पूर्व सुनवाई का अवसर दिया गया है। फिर भी, उन पर लगाए गए प्रतिबंधों के तत्काल और गंभीर परिणाम हुए हैं।

8 जनवरी 2026 को, श्री डोगू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तत्काल अपील प्रकाशित की, जिसमें कहा गया:

“तत्काल: अभी के लिए, मेरे पास किसी भी पैसे तक शून्य पहुंच है। मैं अपने परिवार के लिए भोजन प्रदान नहीं कर सकता, जिसमें 2 नवजात शिशु शामिल हैं, ईयू प्रतिबंधों के कारण। पहले, मुझे जीवित रहने के लिए €506 तक पहुंच दी गई थी जो अब भी दुर्गम है। मेरे बैंक ने इसे ब्लॉक कर दिया। ईयू ने वास्तव में मेरे बच्चों पर भी प्रतिबंध लगा दिया।”

यह बयान **कुल वित्तीय अभाव** की स्थिति का वर्णन करता है, जिसमें बुनियादी आवश्यकताओं को कवर करने के लिए मानवीय छूट के तहत पहले अधिकृत धन तक पहुंच का नुकसान शामिल है। श्री डोगू के अनुसार, उनके बैंक द्वारा इन धन को ब्लॉक करने से वे भोजन खरीदने, आवास या चिकित्सा खर्चों को कवर करने, या अपने परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं, जिसमें दो नवजात शिशु शामिल हैं।

2026 की शुरुआत में, श्री डोगू की स्थिति अनसुलझी बनी हुई है। सितंबर 2025 में प्रतिबंधों के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई थी, और उनकी सूचीकरण के लिए उद्धृत साक्ष्य केवल उनकी पत्रकारिता और सार्वजनिक टिप्पणियों पर आधारित हैं। कोई छूट या मानवीय धन जारी नहीं किया गया है, जो इन उपायों के निरंतर और गंभीर प्रभाव को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण रूप से, पहुंच योग्य धन की कुल अनुपस्थिति ने श्री डोगू को **कानूनी सलाहकार नियुक्त करने में असमर्थ** बना दिया है। परिणामस्वरूप, उनके पास उन पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ कानूनी सलाह प्राप्त करने या न्यायिक उपचार *persequi* करने के व्यावहारिक साधन नहीं हैं। इसलिए वे गंभीर प्रतिबंधात्मक उपायों के अधीन हैं जबकि उनकी वैधता को चुनौती देने में वित्तीय रूप से अक्षम हैं। ईयू प्रतिबंध ढांचे में औपचारिक रूप से एम्बेडेड सुरक्षा उपाय—जो विशेष रूप से ऐसे परिणामों को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं—इस मामले में, संचालित होने में विफल रहे हैं।

श्री डोगू की स्थिति इस निबंध में परीक्षित व्यापक कानूनी समस्या का एक ठोस और तत्काल उदाहरण प्रदान करती है: कैसे ईयू प्रतिबंध, जब कुल अभाव, कानूनी रक्षा की अस्वीकृति, और आश्रित बच्चों को हानि पहुंचाने वाले तरीके से लागू किए जाते हैं, तो वैध निवारक उपाय के रूप में कार्य करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय **न्यायेतर सजा** के रूप में कार्य करते हैं, जो मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों और मानव अधिकार दायित्वों से असंगत हैं।

गंभीर भौतिक अभाव और अमानवीय व्यवहार

मानव अधिकार कानून का एक मौलिक सिद्धांत मानव गरिमा की रक्षा है। उपाय जो किसी व्यक्ति को बुनियादी आवश्यकताओं—भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, और कानूनी सहायता—को पूरा करने की क्षमता से वंचित करते हैं, उस सिद्धांत के मूल को प्रभावित करते हैं।

यूरोपीय मानव अधिकार संधि (ईसीएचआर) का अनुच्छेद 3 अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार को पूर्ण रूप से निषिद्ध करता है। हालांकि पारंपरिक रूप से हिरासत या शारीरिक दुर्व्यवहार से जुड़ा हुआ है, यूरोपीय मानव अधिकार अदालत की न्यायशास्त्र मानती है कि **राज्य-लगाया गया भौतिक अभाव**, जब पर्याप्त रूप से गंभीर और पूर्वानुमान योग्य हो, अनुच्छेद 3 की सीमा तक पहुंच सकता है। कुल संपत्ति फ्रीज जो किसी व्यक्ति को किसी भी पैसे तक पहुंच के बिना छोड़ देता है, मानव गरिमा से असंगत स्थितियां पैदा करता है, विशेष रूप से जहां अभाव लंबे समय तक और अनिवार्य हो।

ये चिंताएं बढ़ जाती हैं जब प्रतिबंध पूर्वानुमान योग्य रूप से **आश्रित बच्चों** को प्रभावित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून, जिसमें बाल अधिकार संधि शामिल है, सभी राज्य कार्रवाइयों में बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिक विचारणीयता के रूप में आवश्यक करता है। प्रतिबंध जो बच्चों को भोजन, आश्रय, या चिकित्सा देखभाल से वंचित करते हैं—भले ही अप्रत्यक्ष रूप से—सामूहिक सजा का एक रूप गठित करते हैं। ऐसे परिणाम न तो आकस्मिक हैं न पूर्वानुमान योग्य नहीं, और इसलिए प्रतिबंध लगाने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी को सक्रिय करते हैं।

ईयू प्रतिबंध ढांचे में निर्मित कानूनी सुरक्षा उपाय

महत्वपूर्ण रूप से, कुल अभाव की गैरकानूनीता केवल बाहरी मानव अधिकार आलोचना का मामला नहीं है; यह **ईयू प्रतिबंध ढांचे के भीतर ही** स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई है। ईयू संपत्ति-फ्रीज विनियमों में नियमित रूप से बाध्यकारी सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं जो धन तक पहुंच की अनुमति देते हैं:

- **बुनियादी आवश्यकताओं** के लिए, जिसमें भोजन, किराया, उपयोगिताएं, चिकित्सा उपचार, और बाल देखभाल शामिल हैं; और
- **उचित पेशेवर शुल्क** के लिए, जिसमें कानूनी सेवाओं से जुड़े खर्च शामिल हैं।

ये छूट वैकल्पिक मानवीय इशारे नहीं हैं बल्कि **कानूनी आवश्यकताएं** हैं, जो ईयू के मौलिक अधिकार चार्टर, ईसीएचआर, और ईयू कानून के सामान्य सिद्धांतों जैसे अनुपातिकता और प्रभावी न्यायिक संरक्षण के तहत दायित्वों को प्रतिबिंबित करती हैं। उनकी समावेश यह स्पष्ट मान्यता गठित करती है कि प्रतिबंध व्यक्तियों को अभाव में कम नहीं करना चाहिए या उनकी खुद को बचाने की क्षमता को बाधित नहीं करना चाहिए।

सुरक्षा उपायों की विफलता और कुल अभाव की गैरकानूनीता

जहां, इन सुरक्षा उपायों के बावजूद, एक प्रतिबंधित व्यक्ति **धन तक शून्य पहुंच** के साथ छोड़ दिया जाता है, जिसमें पहले अधिकृत जीविका भत्ते शामिल हैं, प्रतिबंध अब कानूनी रूप से लागू नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति प्रतिबंध विनियमन का ही **उल्लंघन** गठित करती है, न कि केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रशासनिक परिणाम।

यदि वित्तीय संस्थान या राष्ट्रीय अधिकारी छूट प्राप्त धन तक पहुंच को ब्लॉक करते हैं, तो परिणामी अभाव राज्य और ईयू कानूनी व्यवस्था को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। **कानूनी सेवाओं** के लिए धन तक पहुंच की अस्वीकृति विशेष रूप से गंभीर है: ईयू चार्टर के अनुच्छेद 47 के तहत प्रभावी उपचार का अधिकार न केवल अदालतों तक औपचारिक पहुंच बल्कि उस अधिकार का **व्यावहारिक उपयोग** करने की क्षमता आवश्यक करता है। एक प्रणाली जो किसी व्यक्ति को कानूनी सलाहकार का भुगतान करने से रोकती है, लगाए गए उपायों को सार्थक चुनौती को अक्षम करती है और न्यायिक समीक्षा को खोखली औपचारिकता में बदल देती है।

सुरक्षा उपायों की विफलता विशेष रूप से गंभीर है जहां **बच्चे प्रभावित** हैं। प्रतिबंध ढांचा नाबालिगों की भुखमरी या बेघर होने को अधिकृत नहीं करता। जब ऐसी परिस्थितियों में छूट विफल हो जाती है, उपाय बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत और मानव गरिमा के बुनियादी मानकों से असंगत हो जाते हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, यह विफलता प्रतिबंधों को उनके दावा किए गए **निवारक चरित्र** से वंचित करती है। निवारक उपाय सीमित, अंशांकित, और प्रतिवर्ती होने चाहिए। जब सुरक्षा उपाय ढह जाते हैं और अभाव पूर्ण हो जाता है, प्रतिबंध दबावपूर्ण और दंडात्मक प्रकृति प्राप्त कर लेते हैं, वैध नियामक उपकरणों के बजाय न्यायेतर दंड के रूप में कार्य करते हैं।

उचित प्रक्रिया का अधिकार और प्रभावी न्यायिक संरक्षण

उचित प्रक्रिया संवैधानिक लोकतंत्र का एक आधारशिला है। ईसीएचआर का अनुच्छेद 6 और ईयू चार्टर का अनुच्छेद 47 निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, आरोपों की जानकारी का अधिकार, और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा प्रभावी न्यायिक समीक्षा की गारंटी देते हैं।

ईयू प्रतिबंध व्यवस्थाएं अक्सर इन आवश्यकताओं से कम पड़ती हैं। व्यक्ति कार्यकारी निर्णय द्वारा सूचीबद्ध किए जा सकते हैं जो अज्ञात या अस्पष्ट रूप से व्यक्त आधारों पर आधारित होते हैं, अक्सर गोपनीय खुफिया जानकारी पर निर्भर करते हैं। प्रतिबंध आमतौर पर तत्काल प्रभावी होते हैं, जबकि न्यायिक समीक्षा—यदि उपलब्ध—केवल गंभीर हानि पहले ही हो जाने के बाद होती है।

जहां व्यक्तियों पर कोई आपराधिक अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता और आपराधिक कार्यवाही से जुड़ी प्रक्रियात्मक सुरक्षा से वंचित किया जाता है, फिर भी आपराधिक दंडों के तुलनीय परिणामों के अधीन किया जाता है, प्रतिबंध उचित प्रक्रिया के सार को उल्लंघन करते हैं। यह “पहले सजा, बाद में समीक्षा” संरचना कानून के शासन से मौलिक रूप से असंगत है।

नुल्लुम पोएना सिने लेगे और पूर्वानुमान समस्या

नुल्लुम पोएना सिने लेगे का सिद्धांत, ईसीएचआर के अनुच्छेद 7 में निहित, पूर्व-मौजूद कानून के बिना सजा को निषिद्ध करता है और आवश्यक करता है कि कानूनी मानक पहुंच योग्य और पूर्वानुमान योग्य हों। व्यक्तियों को पहले से समझना चाहिए कि कौन सा आचरण उन्हें दंडात्मक परिणामों के लिए उजागर कर सकता है।

ईयू प्रतिबंध इस सिद्धांत को कमजोर करते हैं जब वे गैर-आपराधिक आचरण को दंडित करते हैं—जैसे वैध पत्रकारिता या राजनीतिक गतिविधि—या जब सूचीकरण मानदंड इतने अस्पष्ट होते हैं कि व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों को उचित रूप से पूर्वानुमान नहीं कर सकते। हालांकि प्रतिबंध औपचारिक रूप से “निवारक” लेबल किए जाते हैं, उनकी गंभीरता, कलंक, और संभावित अनिश्चित कालीन अवधि उन्हें दंड का सार्वभौमिक चरित्र देती है।

कादी बनाम कमीशन में स्थापित सिद्धांतों का पालन करते हुए, ईयू अदालतें आवश्यक करती हैं कि प्रतिबंध साक्ष्य द्वारा समर्थित हों और कथित उद्देश्य के अनुपाती हों। श्री डोगू के मामले में, वैध फिलिस्तीन-समर्थक रिपोर्टिंग को “अस्थिर करने वाला” मानना (केवल व्यापक भू-राजनीतिक कथाओं से कमजोर रूप से जुड़ा) गंभीर अनुपातिकता चिंताएं उठाता है।

कानूनी वर्गीकरण कानूनी वास्तविकता को ओवरराइड नहीं कर सकता। उपाय जो सजा के रूप में कार्य करते हैं, सजा नियंत्रित करने वाले कानूनी बंधनों के अधीन होने चाहिए। अन्यथा अनुमति देना मनमानी शक्ति के खिलाफ सबसे मौलिक सुरक्षा को खोखला कर देता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अप्रत्यक्ष सेंसरशिप

जहां प्रतिबंध पत्रकारिता कार्य या राजनीतिक अभिव्यक्ति से जुड़े होते हैं, अतिरिक्त संवैधानिक उल्लंघन उत्पन्न होते हैं। ईसीएचआर का अनुच्छेद 10 और ईयू चार्टर का अनुच्छेद 11 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, विशेष रूप से राजनीतिक भाषण और पत्रकारिता, जो लोकतांत्रिक समाज में विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति रखते हैं।

पत्रकारिता गतिविधि **उन्नत संरक्षण** का आनंद लेती है, जैसा कि **स्टील एंड मॉरिस बनाम यूनाइटेड किंगडम** में प्रतिबिंबित, विशेष रूप से सार्वजनिक हित के मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय। कार्यकारी आदेश द्वारा लगाया गया वित्तीय अभाव अप्रत्यक्ष सेंसरशिप का प्रभावी रूप कार्य कर सकता है। आपराधिक अभियोजन के विपरीत, यह सार्वजनिक जांच और प्रक्रियात्मक सुरक्षा से बचता है जबकि समान मौन प्रभाव प्राप्त करता है। ऐसी हस्तक्षेप को न्यायोचित नहीं ठहराया जा

सकता जब तक कि यह कानूनी, आवश्यक, और अनुपाती न हो—मानदंड जो तब पूरा नहीं होते जब प्रतिबंध वैध अभिव्यक्ति को दबाते हैं बिना गलती के न्यायिक निष्कर्षों के और कानूनी उपचार तक पहुंच को रोकते हैं।

न्यायेतर सजा के रूप में प्रतिबंध

साथ मिलकर, ये तत्व प्रदर्शित करते हैं कि कुछ ईयू प्रतिबंध व्यवस्थाएं **न्यायेतर सजा** के रूप में कार्य करती हैं। वे गंभीर और व्यक्तिगत हानि लगाती हैं; वे कथित गलती पर आधारित हैं; वे आपराधिक प्रक्रिया को बाइपास करती हैं; और वे प्रभावी सुरक्षा या समयबद्ध न्यायिक नियंत्रण के बिना लागू की जाती हैं।

आपराधिक लेबल की अनुपस्थिति उनकी दंडात्मक प्रकृति को नकारती नहीं है। संवैधानिक और मानव अधिकार कानून उपायों का आकलन उनके **सार और प्रभाव** से करता है, न कि उनके औपचारिक पदनाम से। जब प्रतिबंध आपराधिक दंडों के परिणामों की नकल करते हैं जबकि सजा को वैध बनाने वाली सुरक्षा से बचते हैं, वे शक्ति पृथक्करण को कमजोर करते हैं और कानून के शासन को ही क्षरण करते हैं।

निष्कर्ष

ईयू प्रतिबंध जो कुल वित्तीय अभाव में परिणत होते हैं, कानूनी रूप से अनिवार्य मानवीय और कानूनी-रक्षा छूट तक पहुंच अस्वीकार करते हैं, प्रभावी न्यायिक उपचार बाधित करते हैं, और पूर्वानुमान योग्य रूप से आश्रित बच्चों को हानि पहुंचाते हैं, मौलिक संवैधानिक और मानव अधिकार सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। उनके औपचारिक चरित्रकरण के बावजूद निवारक उपाय के रूप में, ऐसे प्रतिबंध व्यवहार में **न्यायेतर सजा** के रूप में कार्य करते हैं—कानून के बिना, मुकदमे के बिना, और गरिमा के बिना लगाई गई। यदि यूरोपीय संघ अपनी मानव अधिकारों और कानून के शासन की मौलिक प्रतिबद्धता के प्रति वफादार रहना चाहता है, तो प्रतिबंध व्यवस्थाओं को कठोर सार्वभौमिक और प्रक्रियात्मक सीमाओं के अधीन किया जाना चाहिए, सुनिश्चित करते हुए कि कोई व्यक्ति वैध न्यायिक प्रक्रिया की सीमाओं के बाहर सजा न दिया जाए।

संदर्भ

- यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों का चार्टर, 2012 O.J. (C 326) 391।
- मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए संधि (यूरोपीय मानव अधिकार संधि), 4 नवंबर 1950, 213 U.N.T.S. 221।
- बाल अधिकार संधि, 20 नवंबर 1989, 1577 U.N.T.S. 3।
- यूरोपीय संघ की न्यायालय। **कादी और अल बरकात इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाम काउंसिल और कमीशन** (संयुक्त मामले C-402/05 P और C-415/05 P)। 3 सितंबर 2008 का निर्णय।
- यूरोपीय संघ की न्यायालय। **कादी बनाम कमीशन** (मामला C-584/10 P, C-593/10 P, और C-595/10 P)। 18 जुलाई 2013 का निर्णय।
- यूरोपीय मानव अधिकार अदालत। **गोल्डर बनाम यूनाइटेड किंगडम**। 21 फरवरी 1975 का निर्णय।
- यूरोपीय मानव अधिकार अदालत। **एयरी बनाम आयरलैंड**। 9 अक्टूबर 1979 का निर्णय।
- यूरोपीय मानव अधिकार अदालत। **स्टील एंड मॉरिस बनाम यूनाइटेड किंगडम**। 15 फरवरी 2005 का निर्णय।
- यूरोपीय मानव अधिकार अदालत। **एम.एस.एस. बनाम बेल्जियम और ग्रीस**। 21 जनवरी 2011 का निर्णय।
- यूरोपीय मानव अधिकार अदालत। **अल-दुलिमी और मोंटाना मैनेजमेंट इंक. बनाम स्विट्जरलैंड**। 21 जून 2016 का निर्णय।
- यूरोपीय संघ काउंसिल रेगुलेशन (ईयू) नंबर 2024/2642 संघ और उसके सदस्य राज्यों को अस्थिर करने वाली कार्रवाइयों के संबंध में प्रतिबंधात्मक उपायों से संबंधित, जैसा कि संशोधित (उदाहरण के लिए, 2025/965)।
- यूरोपीय आयोग। **ईयू सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति के ढांचे में प्रतिबंधात्मक उपायों (प्रतिबंधों) के कार्यान्वयन और मूल्यांकन पर दिशानिर्देश**। नवीनतम समेकित संस्करण।
- संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समिति। **सामान्य टिप्पणी नंबर 29: आपातकालीन स्थितियां (अनुच्छेद 4)**, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11।
- संयुक्त राष्ट्र विशेष rapporteur अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की संवर्धन और रक्षा पर। **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के प्रभाव पर रिपोर्ट**, A/HRC/45/25।

- बेसेलिक, लियोनार्ड एफ. एम. “मौलिक अधिकारों की रक्षा पोस्ट-लिस्बन: यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकार चार्टर और यूरोपीय मानव अधिकार संधि के बीच अंतर्क्रिया।” **कॉमन मार्केट लॉ रिव्यू** 49, नंबर 4 (2012): 1315-1346।
- एकेस, क्रिस्टीना। **ईयू काउंटर-टेररिस्ट प्रतिबंध और मौलिक अधिकार: व्यक्तिगत प्रतिबंधों का मामला।** ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2009।
- गिल्ड, एल्सपेथ, और सर्जियो कैरेरा। “प्रतिबंध और उचित प्रक्रिया।” **यूरोपीय लॉ जर्नल** 16, नंबर 2 (2010): 157-176।